THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAYAN PRASAD NISHAD): (a) No proposal to put a blanket ban on setting up of industries in forest is under consideraiton of the Government.

(b) Does not arise.

(c) No. Sir. However, the National Forest Policy, 1988 stipulates that as far as possible, the forest based industry should raise the raw material needed for meeting its own requirements, preferably by establishment of a direct relationship, between the factory and the individuals who can grow the raw material by supporting the individuals with imnputs including credit, constant technical advise and finally harvesting and transport services.

(b) Does not arise.

Gauge conversion in Gujarat

3987. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Gujarat for conversion of metre gauge/ narrow gauge lines into broad gauge;

(b) if so, the details thereof and the decision taken by Government thereon;

(c) whether Government propose to take up gauge conversion projects in Gujarat through private funding; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (d) Yes, Sir. Proposals were received from the Govt, of Gujarat for conversion of Rajkot-Veraval, Navalakhi-Wankaner-Maliya, Surendranagar-Bhavnagar, Viramgam-Mahesana-Patna, Bedi Port, Surendranagar-Rajula, Kalol-Vijapur, Ahmedabad-Himmatnagar, Dhrangadhra-Kuda, Gandhidham-Bhuj, Joravarnagar-Sayala and Bharuch-Dahej. Out of these, Gauge Conversion of Wankaner-Dahinsara-Navlakhi and Dahinsara-Maliya Miyana and Viramgam-Mahesana has been taken up through private Capital under the BOLT Scheme.

Gauge Conversion of Gandhidham-Bhuj and Rajkot-Veraval sections have also been taken up.

कृषि क्षेत्र में योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

3988. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर सरकारी संगठनों ने सरकार से कृषि क्षेत्र में योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन संगठनों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों की जांच-पड़ताल कर रही है;

(ग) योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कब तक आरंभ कर दिया जाएगा; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (घ) विकेन्द्रीकृत योजना एक सतत् प्रक्रिया है। हालांकि कृषि क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है फिर भी, योजना को सबसे निचले स्तर पर लागू करने के लिए विभिन्न हलकों से प्राप्त विभिन्न मांगों को देखते हुए 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अधिनियमन के माध्यम से सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इन संविधान संशोधन अधिनियमों से पचांयतों तथा नगरपालिकाओं को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए योजना तैयार करने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों को प्रभावी बनाने की कार्रवाई विभिन्न राज्यों में अलग-अलग चरणों में है।

Production of Sugarcane in Haryana, U.P. and Maharashtra

3989. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the production of sugarcane in the States of Ha-yana, Uttar Pradesh and Maharashtra, separately, during the last two years; -

(b) the details of assistance provided by Government to the aforesaid States for increasing the production of sugarcane; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The production of sugarcane in the States of Haryana, Uttar Pradesh and Maharashtra during the last two years i.e. 1994-95 and 1995-% (likely) is as follows:

(Million tonnes)

States	1994-95	1995-96
Haryana Uttar	7.01	7.50
Pradesh	109.91	112.84
Maharashtra	44.26	44.28

(b) For increasing the production of sugarcane, the following assistance has been provided by the Centre under the scheme, viz., Sustainable Development of Sugarcane based Cropping System Areas:—

(Rs. in lakhs)

States	1995-96 (Amount Released)	1996-97 (Outlay)
Haryana Uttar	112.82	90.63
Pradesh	810.29	671.70
Maharashtra	507.12	439.37

(c) In order to increase the production and productivity of sugarcane, a centrally sponsored scheme "Sustainable Development of Sugarcane base Cropping System Areas (SUBAC)" was initiated in 1995-96 and is being implemented in 21'. StatesVnion Territories including Haryana, Uttar Pradesh and Maharashtra on 75:25 sharing basis.

केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को ऐच्छिक विषय बनाना

3990. श्री शिवचरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालयों और पूर्व के संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के अधीनस्थ विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू किए जाने के संबंध में सितम्बर, 1972 में कतिपय दिशानिर्देश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इन दिशा-निर्देशों की उपेक्षा कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राव सैकिया): (क) और (ख) शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.9.72 को जारी किए गए पत्र में केन्द्रीय बोर्ड का निर्णय सूचित कर दिया गया है। विद्यालयों में इस विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने के लिए विशिष्ट निर्देश नहीं दिये गए है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Number of Chemicals & Fertilizer Units

3991. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of CHEMICLAS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of chemicals and fertilizers units in the country in the public and private sectors;

(b) the number of them that have turned sick and since when; and

(c) the efforts made, if any, to make sick units viable and results thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICLAS & FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) Details of fertilizer